सेवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह बनी

एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप से डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त आधार मिला

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त आधार मिला है. इससे नागरिक सेवाएं अब अधिक सरल, सुगम और सुलभ हुई हैं.

डिजिटल तकनीक आज सुशासन की आधारशिला बन चुकी है और प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नई पहचान स्थापित कर रहा है. अब प्रदेशवासियों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही मंच पर सभी सुविधाएँ सहज, त्वरित और पारदर्शी रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस पहल से सेवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और सुव्यवस्थित बनी है. साथ ही नागरिकों के समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित हुई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एकीकृत नागरिक सेवा मंच 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एक ही डिजिटल विंडो पर उपलब्ध करा रहा है. वर्ष 2026 तक 100 प्रतिशत ई-सेवा डिलीवरी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सेंटर फॉर एक्सीलेंस द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म नागरिकों, विभागों एवं सेवाओं को एकीकृत डिजिटल इको-सिस्टम में जोड़ते हुए सुशासन को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने में सहायक सिद्ध होगा. 'एमपी ई-सेवा' को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है.

एकीकृत पोर्टल पर सभी सेवाएं

एमपी ई-सेवा पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को बार-बार अलग-अलग पोर्टल पर जाने और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता समाप्त की गई है. नागरिक अब ई सेवा. एमपी .जीओव्ही .इन और मोबाइल ऐप के माध्यम से पात्रता जांच, आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और अनुमोदन जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं. पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-साइन और डिजिटल प्रमाणपत्र की व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और फेसलेस बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है.

प्रत्येक परिवार को 8 अंकीय परिवार आईडी और हर सदस्य को 9 अंकीय सदस्य आईडी दी गई है. इससे ऑटो-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को सक्षम बनाया गया है. इससे पात्रता निर्धारण स्वतः हो जाता है और अनावश्यक देरी व दोहराव समाप्त होता है. पोर्टल की प्रमुख विशेषता 'ऑटो-फेचिंग डॉक्युमेंट्स' है, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहती. एक बार अपलोड किए गए दस्तावेज आगे की सेवाओं में स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं.

मंत्रालय के गलियारे से

कन्हैया लोधी

अफसरों में बेचैनी

पिछले दिनों आईएएस अफसरों के थोकबंद तबादले हुए. इस सूची में ज्यादातर जिलों की कमान संभालने वाले अफसर थे. इस सूची के बाद अब मंत्रालय में सर्जरी की सूची की प्रतीक्षा होने लगी है. इस सूची को लेकर अब मंत्रालय में पदस्थ कुछ आला अफसरों में बेचैनी को साफ महसूस किया जा सकता है. दरअसल इस सूची में कई अफसरों को लूप लाइन में भेजा जा सकता है. वहीं जिम्मेदार और कामदार अफसरों को और जिम्मेदारी दी जा सकती है. वहीं विवादित अफसरों को भी मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. अब देखना ये है कि अफसरों के संकट से जूझ रही सरकार इस मंसूबे में कितना कामयाब हो पाती है.

ज्वॉइनिंग को लेकर पेंच

सचिव स्तर के दो अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है, लेकिन दोनों ही अफसर अपने नये दायित्व को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं. न तो ये रिलीव हो रहे हैं और न ही दूसरे ही अधिकारी रिलीव हो रहे हैं. दोनों को ही एक-दूसरे की कुर्सी संभालना है. दोनों ही जहां पदस्थ हैं, वे बड़े महकमे में शुमार है. बहरहाल दोनों ही जगह मातहतों को नए साहब का इंतजार है.

नेताजी का शक्ति प्रदर्शन

प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार एक कद्दावर मंत्री आने वाले दिनों में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं. इसकी तैयारी पूरे प्रदेश में चल रही है. राजधानी में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रदेश भर से लोग बुलाए जा रहे हैं. संभवतः ये पहली बार होगा कि जब वे इस तरह का अघोषित शक्ति प्रदर्शन करेंगे. बताया जा रहा है कि ये किसी समाज द्वारा राजधानी में बिना किसी सरकारी सहयोग के किया जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम हो सकता है. इसकी तैयारी ठीक उसी तरह चल रही है जिस तरह विशाल मैदान में बड़े सरकारी सम्मेलन की चलती है. इस शक्ति प्रदर्शन का नेताजी को क्या फायदा मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में ही है.

पूर्व मंत्री का मेला

प्रदेश के एक पूर्व मंत्री एक बार फिर राजधानी में नये सिरे से जमावट की कोशिशों में है. लंबे समय से वे मुख्य धारा से बाहर चल रहे हैं. कभी उन्हें दिवंगत पूर्व सीएम का बेहद करीबी माना जाता था, उनके अवसान के बाद पूर्व मंत्री जी का राजनीतिक भविष्य भी डगमगाने लगा. लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने राजधानी में सक्रियता दिखाने के लिए एक मंच तलाश ही लिया. उन्होंने एक भव्य समर मेले का आयोजन किया है. जिसमें आए दिन कोई न कोई व्हीआईपी पहुंच रहे हैं. ऐसे में साहब को लाईम लाइट में आने का फिर मौका मिल रहा है. इसका फायदा उन्हें निकट भविष्य में किस तरह मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा.

टूटेगा माधवनगर थाना, स्टॉफ होगा नए स्थान पर रवाना

- एक परिसर में पूरा प्रशासन, उज्जैन में बन रहा अनोखा संयुक्त भवन
- 134 करोड़ की परियोजना से बदलेगा प्रशासनिक सिस्टम

नवभारत न्यूज

उज्जैन. सिंहस्थ से पूर्व प्रशासनिक और शहरी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है. फ्रीगंज क्षेत्र में कलेक्टर और एसपी के संयुक्त बहुमंजिला भवन के निर्माण के साथ ही माधवनगर थाने को भी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है. यह बदलाव न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आसान बनाएगा, बल्कि शहर की पार्किंग और यातायात समस्या को भी काफी हद तक सुलझाएगा.

फ्रीगंज में वर्तमान एसपी कार्यालय के सामने लगभग 134.97 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त प्रशासनिक भवन बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जा चुका है. यह भवन भूतल सहित सात मंजिला होगा, जिसमें 21 विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे. दो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर मल्टीलेयर पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, जिससे क्षेत्र में लंबे समय से महसूस की जा रही पार्किंग की समस्या को राहत मिलेगी.

थाने की बिल्डिंग भी बनेगी-नई व्यवस्था के तहत भविष्य में माधवनगर थाने की भी आधुनिक बिल्डिंग तैयार होगी, जिससे पुलिस कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बन सकेगी.

2 साल में बनेगी कलेक्टर, एसपी कार्यालय की बिल्डिंग - संयुक्त प्रशासनिक भवन के निर्माण की जिम्मेदारी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (बीडीसी) को दी गई है. करीब 35 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले इस भवन में सैकड़ों कक्ष, बैठक कक्ष, वीसी रूम, केंटीन, लिफ्ट और आधुनिक अग्निशमन व्यवस्था भी होगी. अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना अगले दो वर्षों में पूरी होने की संभावना है.

थाना भी होगा शिफ्ट

इस योजना के चलते माधवनगर थाना, जो वर्तमान में इसी क्षेत्र में स्थित है, जहां एसपी कलेक्टर की नई बिल्डिंग बन रही है, वहां से थाने को हटाया जाएगा. थाना भवन की जमीन पर भविष्य में पार्किंग एवं बाग-बगीचे विकसित करने की योजना है. यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों से भरा हुआ है, जहां पुलिस कॉलोनी, दशहरा मैदान और रहवासी कॉलोनी के कारण आवागमन का दबाव अधिक रहता है.

जाल सेवा स्कूल की जमीन तय

माधवनगर थाने को अस्थायी रूप से घास मंडी चौराहा, फ्रीगंज स्थित शासकीय श्री जाल सेवा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में शिफ्ट किया जाएगा. वर्ष 1975 से संचालित यह स्कूल वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक संचालित है. इसे सीएम राइज योजना के तहत करीब 39 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है. स्कूल के पुराने हिस्से की खाली जमीन पर पहले अस्थायी और बाद में स्थायी रूप से थाना भवन का निर्माण किया जाएगा.

ग्वालियर को मिलीं चार स्पेशल ट्रेनें

ग्वालियर, 18 अप्रैल. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है. ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज जाने के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो 11 जुलाई तक जारी रहेगी. ये ट्रेनें निम्नानुसार हैं.. दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया से आज मंत्रालय में जाकर ग्वालियर के पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल ने भेंट की थी. वहीं पर सिंधिया ने नई रेलों संबंधी यह जानकारी साझा की. सिंधिया द्वारा ग्वालियर डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन में सदस्य बनाए जाने पर रमेश अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी, ग्वालियर को एक नवीन हवाई सेवा जो बेंगलुरु दिल्ली ग्वालियर एवं ग्वालियर दिल्ली से बेंगलुरु से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ होने जा रही है, उसके लिए धन्यवाद दिया. रमेश अग्रवाल जी ने सिंधिया से निवेदन किया कि एक नया हवाई सेवा हैदराबाद से ग्वालियर और ग्वालियर से हैदराबाद के लिए चालू कराई जाए.

कांग्रेस ने आगामी रणनीति पर किया मंथन

कांग्रेस ने की संगठन की तैयारियों की समीक्षा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 18 अप्रैल. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को भोपाल स्थित इंदिरा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें सभी जिला प्रभारियों को शामिल कर संगठन की तैयारियों की समीक्षा की गई और आगामी रणनीति पर मंथन किया गया.

बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की. इस दौरान वरिष्ठ नेताओं में उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे, संगठन महासचिव संजय कमले, एआईसीसी सचिव उषा नायडू और संजय दत्त सहित जिला स्तरीय समन्वयक मौजूद रहे.

बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए आगामी कार्यक्रमों के लिए रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई. नेताओं ने गांव-गांव तक जनसंपर्क बढ़ाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और स्थानीय इकाइयों को मजबूत बनाने पर जोर दिया. जिला प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने, जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और पार्टी की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए. बैठक में आने वाले महीनों में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय भी लिया गया, जिसका उद्देश्य पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना और राज्य में समर्थन आधार को मजबूत करना है.

रीवा में बैंकों में बढ़ेगी चौकसी

रीवा. सिंगरौली में हुई बैंक डकैती के बाद रीवा अलर्ट मोड में आ गया है. बैंकों की चौकसी बढ़ेगी. इसके साथ ही बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने बैंक अधिकारियों से चर्चा की गई. इसके साथ ही सभी बैंको की सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारियों ने निरीक्षण किया. जहां सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, अलार्म सिस्टम आदि का निरीक्षण किया गया, जिस बैंक में कमी पाई गई वहा बैंक प्रबंधन को तत्काल सुधार कार्रवाई के लिए निर्देश किया गया. गौरतलब है कि सिंगरौली में हुई बैंक डकैती के बाद बैंको की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

अलर्ट : इंदौर से उज्जैन तक पारा 41 डिग्री के पार

भोपाल, 18 अप्रैल. मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 16 से ज्यादा जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है. इंदौर और उज्जैन में भी मौसम पूरी तरह से गर्म बना हुआ है.

यहां का तापमान 41 डिग्री के पार चला गया है. शनिवार को तापमान 43 डिग्री तक हो गया है. मालवा-निमाड़ इस वक्त ज्यादा तप रहा है. मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भीषण लू चलने का अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में सुबह से ही मौसम की मार देखी जा रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम विभाग डुके मुताबिक इंदौर संभाग के ज्यादातर जिलों में लू चलने की संभावना है. खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिलों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है. यहां का तापमान 42 डिग्री के उपर जा चुका है.

एमपी के 9 शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास चला गया है. मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ज्यादातर जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में इंदौर और उज्जैन संभाग के ज्यादातर जिलों में प्रशासनिक स्तर पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और स्कूल सुबह से खोलने के निर्देश दिए हैं. क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से परेशानियां ज्यादा हो रही हैं.

प्रदेश में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाए. छतरपुर के खजुराहो में पारा सबसे ज्यादा 43.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. वहीं, उमरिया में 42.9 डिग्री, टीकमगढ़-नौगांव में 42.8 डिग्री, नौगांव में 42.6 डिग्री, मंडला में 42.5 डिग्री, दमोह, गुना-दतिया में 42.2 डिग्री, सागर-सतना में 41.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 41.6 डिग्री, सेल्सियस दर्ज किया गया.

पेज एक का शेष

रेलवे-इंश्योरेंस समेत 5 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

विश्वसनीयता में सुधार आएगा. रेलवे के इस विस्तार से करीब 180.31 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 7.33 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है. इसके साथ ही, इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण बस्तियों को कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. इसके लिए कुल वित्तीय परिव्यय बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपये कर दिया गया है. मैदानी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के शेष कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है. वहीं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों के निर्माण की अवधि मार्च 2029 तक विस्तारित की गई है.

दलों के बीच नैरेटिव युद्ध में फंसा महिलाओं का अधिकार

पर विपक्षी आरोपों को कुंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी विपक्षी तेवर से भ्रम कायम है. राजनीतिक रूप से देखें तो, सरकार ने इस विधेयक के जरिए महिला मतदाताओं के बीच एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन परिसीमन और जनगणना के साथ इसे नत्थी कर देने से जो क्रेडिट वॉर शुरू हुआ है, उसने इस कानून की चमक को कुछ फीका जरूर किया है. जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि संसद ने दरवाजे तो खोल दिए हैं, लेकिन प्रवेश के लिए अभी एक लंबा और अनिश्चित इंतजार बाकी है.

महिला एवं बाल विकास टीम ने रोका बाल विवाह

जबलपुर. बरेला थाना अंतर्गत जुनवानी कंचनपुर टोला में15 साल की बालिका दुल्हन बनने वाली थी. 20 अप्रैल को बालिका का विवाह कराया जा रहा था. जैसे ही जिसकी भनक लगते महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया. परिवार ने अब 18 साल के बाद शादी का आश्वासन दिया है. सेक्टर पर्यवेक्षक नीरजा वर्मा को सूचना मिली थी कि ग्राम जुनवानी की बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा है. शनिवार को जाँच दल गांव पहुंचा. जांच में पाया गया कि बालिका के आधार कार्ड में जन्म तिथि 01 जनवरी 2012 और जन्म प्रमाण पत्र में 29 जनवरी 2011 दर्ज है. इस हिसाब से बालिका की उम्र लगभग 15 वर्ष है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7590/60**